भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3697
बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>आंध्र प्रदेश में पीएम-कुसुम के अंतर्गत परियोजनाएं</u>

3697. डॉ. बायरेड्डी शबरीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश सहित देश भर में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या के संबंध में आंकड़े हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में पीएम-कुसुम के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) नान्दयाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएम-कुसुम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) नान्दयाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पीएम-कुसुम का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांगों के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य सहित, पीएम-कुसुम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति अनुलग्नक में दी गई है।

(ख) से (घ): पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्रों और घटक-ख के अंतर्गत स्टैंडअलोन सौर पंपों के लिए नंदयाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश राज्य से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। घटक-ग के लिए, राज्य ने फीडर स्तरीय सौरीकरण के अंतर्गत पंपों की मांग की है। हाल ही में, मंत्रालय ने उपलब्ध क्षमता के आधार पर राज्य को 1 लाख पंप आवंटित किए हैं।

लाभार्थी चयन की जिम्मेदारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) की है।

पीएम-कुसुम योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर व्यापक आउटरीच और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इसमें कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के साथ समय-समय पर समीक्षा और सहयोगात्मक बैठकें भी शामिल हैं।

अनुलग्नक

'आंध्र प्रदेश में पीएम-कुसुम के अंतर्गत परियोजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3697 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम-कुसुम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति (दिनांक 13.12.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	घटक-क (मेगावाट)		घटक-ख (संख्या)		घटक-ग (संख्या)		
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत (आईपीएस)	स्वीकृत (एफएलएस)	स्थापित (कुल)
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	100000	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	700	394	0	0	0
3	असम	10	0	4000	0	1000	0	0
4	छत्तीसगढ़	30	4	10000	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	0	0	0	70000	0
6	गुजरात	500	0	12382	7705	0	725000	30158
7	गोवा	150	0	900	80	0	11000	700
8	हरियाणा	85	6.65	197655	137594	0	12899	0
9	हिमाचल प्रदेश	100	25.95	1270	685	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	20	0	5000	1937	4000	0	0
11	झारखंड	20	0	42985	23999	1000	0	0
12	कर्नाटक	0	0	41360	1674	0	766588	1713
13	केरल	1.5	0	8	8	45100	25387	7402
14	लद्दाख	0	0	1400	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	1490	39.63	59400	7325	0	445000	7417
16	महाराष्ट्र	700	6	505000	222933	0	775000	31428
17	मणिपुर	0	0	150	78	0	0	0
18	मेघालय	0	0	3035	96	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	1700	40	0	0	0
20	नागालैंड	5	0	265	65	0	0	0
21	ओडिशा	500	0	16441	5478	25000	10000	0
22	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	220	0	33000	12952	186	95000	0
24	राजस्थान	1550	244	162914	89245	6418	400000	5476
25	तमिलनाडु	424	1	5200	3909	5000	6000	0
26	तेलंगाना	4000	0	0	0	28000	0	0
27	त्रिपुरा	5	0	10895	3537	2600	0	50
28	उत्तर प्रदेश	151	0	110948	54117	12000	94000	2000
29	उत्तराखंड	0	0	5685	473	200	0	0
30	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	700	0	20
31	अंडमान और निकोबार	0	0	34	0	436	0	0
	कुल	9961.50	327.23	1232327	574324	131640	3535874	86364

*****